

संक्षिप्त समाचार

बेतिया राज की जमीन पर बाउंड्री निर्माण रोका



बीएनएम @ बेतिया। नरकटियागंज नगर के वार्ड संख्या-12 स्थित प्रकाश नगर में बेतिया राज की जमीन पर बाउंड्री निर्माण की सूचना मिलने पर अंचल प्रशासन ने तत्काल काम रुकवा दिया। बुधवार को राजस्व अधिकारी अशोक कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य बंद कराने का निर्देश दिया। संबंधित जमीन खाता संख्या-8 और खेसरा संख्या-259 के अंतर्गत है। राजस्व अधिकारी के अनुसार, करीब 25 धुर जमीन पर मुन्ना सिंह द्वारा बाउंड्री का निर्माण कराया जा रहा था। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बेतिया राज की जमीन पर बिना वैध अनुमति निर्माण या अवैध कब्जे का प्रयास करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

महिला से 50 हजार की ठगी

बीएनएम @ बेतिया। नरकटियागंज में सेंट्रल बैंक से रुपये निकालकर घर जा रही शमीमा खातून से उच्चकों ने 50 हजार रुपये ठग लिए। महिला ने थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। बताया जाता है कि बैंक में फॉर्म भरवाने के दौरान एक युवक उससे मिला, जबकि दूसरा बातचीत करने लगा। बैंक से बाहर निकलने पर दोनों ने उसे कागज का बंडल थमा दिया और झोले में रखने के बहाने उसके 50 हजार रुपये लेकर फरार हो गए। बाद में महिला ने बंडल खोला तो उसमें केवल 500 रुपये का एक नोट मिला। थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जाएगी।

पत्नी की मौत के मामले में पति को 10 साल की कैद



बीएनएम @ बगहा / पश्चिम चंपारण। बगहा व्यवहार न्यायालय ने वर्ष 2017 में रामनगर थाना क्षेत्र में पत्नी की मौत से जुड़े मामले में पति रंजीत चौधरी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्रा की अदालत ने 14 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाते हुए सास दयमंती देवी और ससुर मथुरा प्रसाद को भी तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। पति को धारा 498ए के तहत भी तीन वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। सास-ससुर को भी इस धारा में तीन-तीन वर्ष की कैद और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। मामला रामनगर थाना कॉड संख्या 28/2017 से संबंधित है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार भारती ने पैरवी की।

शराब के साथ कई गिरफ्तार, 15 वारंट निष्पादित

बीएनएम @ बगहा / पश्चिम चंपारण। बगहा पुलिस ने शराबबंदी कानून और अपराध निर्वणण को लेकर विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए शराब, बाइक और मोबाइल बरामद किए। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के अनुसार, वनहा थाना क्षेत्र से 63 लीटर देशी शराब, एक बाइक और एक मोबाइल बरामद किया गया। सेमरा थाना पुलिस ने पांच लीटर और पित्तहां थाना पुलिस ने नौ लीटर देशी शराब के साथ आरोपितों को पकड़ा। अन्य थाना क्षेत्रों में भी विभिन्न मामलों में गिरफ्तारियों की गईं। नौरगिया थाना क्षेत्र के नौ आरोपितों को रि कॉल पर मुक्त किया गया। अभियान के दौरान 15 वारंट और एक कुकी का निष्पादन किया गया। वाहन जांच में 400 वाहनों की जांच कर नियमों के उल्लंघन पर 94 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया।

दिलशाद की मौत पर तेजस्वी ने परिवार से की वीडियो कॉल, न्याय का भरोसा

बीएनएम @ पश्चिम चंपारण। पुलिस हिरासत में दिलशाद अंसारी की मौत के मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने मंगलवार शाम वीडियो कॉल कर पीडित परिवार से बातचीत की और जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिया। पत्रजनों ने पुलिस पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। उनके अनुसार, 12 अक्टूबर की रात करीब दो बजे पुलिस दिलशाद को घर से गिरफ्तार कर ले गई थी। वहीं, पुलिस का कहना है कि थाने ले जाने के दौरान वह चलती गाड़ी से कूद गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी और इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मामले में सहोदरा थानाध्यक्ष समेत छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। घटना की जांच जारी है। अब निष्पक्ष जांच से ही दिलशाद की मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।

नेपाल में गैस सिलेंडर फटने से तीन घायल, एक भारतीय शामिल

बीएनएम @ वाल्मीकिनगर / पश्चिम चंपारण । पड़ोसी देश नेपाल के नवलपरासी जिले में सोमवार शाम दो अलग-अलग स्थानों पर गैस सिलेंडर फटने से एक भारतीय नागरिक समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सितंबर के अंतिम सप्ताह में गंडक नदी में आई बाढ़ के दौरान बहकर आए गैस सिलेंडरों को नदी से निकालकर कबाड़ियों को बेचा गया था। इसी दौरान गंडक बराज के 36 नंबर फाटक के पास रानीनगर जाने वाले रास्ते पर सिलेंडर अचानक फट गया, जिससे उनका बायां हाथ बुरी तरह जखमी हो गया। उन्हें पहले वाल्मीकिनगर के एक निजी क्लीनिक में ले जाया गया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद अनुमंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया गया। दूसरी घटना पूर्वी नवलपरासी जिले की कवासोती नगरपालिका के वार्ड संख्या 17 स्थित अमलटांडी में हुई। मध्यबिंदु नगरपालिका निवासी 49 वर्षीय कासी बोटे गंडक नदी के किनारे से निकाला गया सिलेंडर बेचने के लिए 28 वर्षीय कबाड़ी सचिन कुमार के पास पहुंचे थे। सिलेंडर को हेंक्सा ब्लेड से काटने के दौरान अचानक विस्फोट हो गया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए भरतपुर स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार हुई इन घटनाओं के बाद बाढ़ में बहकर आए सिलेंडरों को बिना जांच के खरीदने और काटने के खतरों को लेकर चिंता बढ़ गई है।

गैस सिलेंडर ब्लास्ट, दुकान का सामान जलकर राख

बीएनएम @ पश्चिम चंपारण। मझौलिया प्रखंड की करमवा पंचायत स्थित देवान चोक पर बुधवार दोपहर गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद जोरदार धमाका हो गया। हादसे में दुकानदार संदीप कुशावाहा की दुकान में रखा सामान और फ्रिज जलकर राख हो गया। संदीप कुशावाहा दुकान में पकौड़े बना रहे थे, तभी सिलिंडर में आग लग गई। खतरा भांपकर वह समय रहते दुकान से बाहर निकल गए, जिससे उनकी जान बच गई। स्थानीय लोगों ने काफी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया। घटना की सूचना अंचलधिकारी डॉली कुमारी को दी गई है। उन्होंने नुकसान का जायजा लेकर नियमानुसार मुआवजे की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही है। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

रामगढ़वा में प्रभार का खेल, निदेशक के आदेश की अनदेखी

बीएनएम @ विजय कुमार

रामगढ़वा: प्रखंड में मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रभार को लेकर शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि राज्य और जिला स्तर के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद वरीयता के निर्धारित नियमों की अनदेखी की जा रही है। कई विद्यालयों में वरीय शिक्षकों की मौजूदगी के बावजूद कनिष्ठ शिक्षक प्रभार संभाले हुए हैं, जबकि वरीय शिक्षक न्याय की उम्मीद में विभागीय कार्यालयों का चक्कर काटने को मजबूर हैं। मामला केवल प्रशासनिक उदासीनता तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे शिक्षा विभाग के आदेशों के अनुपालन और जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभागीय व्यवस्था पर कथित तौर पर बाहरी प्रभाव हावी है, जिसके कारण प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश भी जमीन पर प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। ताजा मामला प्रखंड क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय, रघुनाथपुर का है। यहां वरीय स्नातक ग्रेड शिक्षकों के रहते बेसिक ग्रेड के शिक्षक के प्रभार में बने रहने का मामला सामने आया है। संबंधित शिक्षक का दावा

वरिष्ठ शिक्षकों की मौजूदगी में कनिष्ठों को प्रभार, दस से अधिक मध्य विद्यालयों में नियमों की अनदेखी का आरोप



है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देशानुसार स्नातक ग्रेड के वरीय शिक्षक की उपलब्धता में बेसिक ग्रेड के शिक्षक को प्रभार देना नियमसम्मत नहीं है। विद्यालय के वरीय शिक्षक रत्नेश तिवारी को प्रभार सौंपने संबंधी पत्र जारी किया था। साथ ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अपनी देखरेख में आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, संबंधित पक्ष का आरोप

इसके बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। रत्नेश तिवारी के मुताबिक, लगातार शिकायतों और प्रयासों के बाद 13 जुलाई को जिला शिक्षा पदाधिकारी, मोतिहारी ने शिक्षिका ललिता कुमारी को प्रभार सौंपने संबंधी पत्र जारी किया था। साथ ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अपनी देखरेख में आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, इस संबंध में संबंधित

है कि आदेश जारी होने के बावजूद अब तक उस पर अमल नहीं किया गया है। इस मामले में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आरोप है कि न तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराया गया और न ही आदेश के अनुपालन में आ रही बाधाओं अथवा अनुपालन नहीं होने की स्थिति से जिला कार्यालय को अवगत कराया गया। हालांकि, इस संबंध में संबंधित

अधिकारियों का पक्ष सामने आना शेष है। ग्रामीणों का दावा है कि प्रभार से जुड़ी अनियमितता केवल रघुनाथपुर विद्यालय तक सीमित नहीं है। रामगढ़वा प्रखंड के दस से अधिक मध्य विद्यालयों में वरीयता की अनदेखी कर प्रभार दिए जाने की शिकायतें हैं। यदि इन आरोपों की पुष्टि होती है, तो यह शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था और आदेशों के पालन पर गंभीर प्रश्नचिह्न होगा। विद्यालयों में प्रभार को लेकर विवाद और खींचतान का सीधा असर शैक्षणिक माहौल पर पड़ने की आशंका है। जिस व्यवस्था का उद्देश्य विद्यालयों का सुचारु संचालन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है, वही यदि विवादों में उलझ जाए, तो इसका खामियाजा अंततः विद्यार्थियों को भुगतना पड़ सकता है। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि जब जिला स्तर से प्रभार सौंपने का आदेश जारी किया जा चुका है, तो उसके अनुपालन में देरी हो रही है क्यों ? यदि आदेश के बावजूद संबंधित विद्यालय में स्थिति नहीं बदली है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या विभागीय स्तर पर आदेशों की

निगरानी और जवाबदेही तय करने की व्यवस्था प्रभावी ढंग से काम कर रही है? शिक्षा विभाग के लिए यह मामला केवल प्रभार विवाद नहीं, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और नियमसम्मत कार्यप्रणाली की परीक्षा भी है। वरीयता के नियमों का पालन सुनिश्चित करना और जारी आदेशों को समयबद्ध तरीके से लागू कराना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। अब आवश्यकता है कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग मामले की निष्पक्ष जांच कराएं, संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब करें और शिकायतों की सत्यता के आधार पर उचित कार्रवाई करें। साथ ही, जिन विद्यालयों में वरीयता के नियमों की अनदेखी की शिकायतें हैं, वहां अभिलेखों की जांच कर नियमानुसार प्रभार व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आखिरकार, सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था आदेशों और नियमों से चलनी चाहिए, न कि कथित प्रभाव, मनमानी या विभागीय उदासीनता से। शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि निदेशक और जिला स्तर के आदेश केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका अनुपालन धरातल पर भी दिखाई दे।

कार से 59 चोरी के मोबाइल बरामद,पांच गिरफ्तार



बीएनएम @ मेहसी(पूर्वी चंपारण)

जिले में पुलिस ने चोरी के मोबाइल की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एनएच-27 पर एक कार से 59 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस दौरान तीन पुरुष और दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है। पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 13 अक्टूबर

की रात गश्ती और विशेष छापेमारी के दौरान सूचना मिली कि सफेद रंग की किआ सोनेट कार (बीआर-05-बीयू-4338) से चोरी के मोबाइल मुजफ्फरपुर से मोतिहारी होते हुए नेपाल ले जाए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर वरीय पुलिस पदाधिकारियों के निर्देश पर ग्राम दामोदरपुर कट के पास एनएच-27 पर वाहन जांच शुरू की गई। इसी दौरान संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली गई,

जिसमें 59 मोबाइल फोन बरामद हुए। पुलिस ने चालक समेत कार में सवार पांचों लोगों को गिरफ्तार कर मोबाइल और वाहन जब्त कर लिया। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस चोरी के मोबाइल की खरीद-बिक्री और नेपाल तक तस्करी करने वाले नेटवर्क का पता लगाने के लिए अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी कर रही है।

घोड़ासहन, रीणा और बैरगनिया को रेलवे की बड़ी सौगात, कई एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को मिली मंजूरी

दिल्ली, हैदराबाद और तिरुपति जाने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत, प्रायोगिक आधार पर शुरू होगा ट्रेनों का ठहराव

बीएनएम @ घोड़ासहन

सीमावर्ती क्षेत्र के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। वर्षों से लंबी दूरी की प्रमुख ट्रेनों के ठहराव की मांग अब पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ी है। रेलवे बोर्ड ने घोड़ासहन, रीणा और बैरगनिया रेलवे स्टेशनों पर कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों के प्रायोगिक ठहराव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से स्थानीय यात्रियों को दिल्ली, हैदराबाद और तिरुपति सहित देश के विभिन्न हिस्सों तक आवागमन में सुविधा मिलेगी। वहीं, व्यापारियों, नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और अन्य यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगी की उम्मीद है। रेलवे बोर्ड से मिली मंजूरी के अनुसार, घोड़ासहन स्टेशन पर लोकहा बाजार—आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन का ठहराव होगा। वहीं, रीणा स्टेशन पर

हैदराबाद—रक्सौल एक्सप्रेस और दरभंगा—गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस को ठहराव की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, बैरगनिया स्टेशन पर तिरुपति—रक्सौल एक्सप्रेस का ठहराव स्वीकृत किया गया है। **स्वीकृत ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है—**
घोड़ासहन स्टेशन: ट्रेन संख्या 04013/04014, लोकहा बाजार—आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल।
रीणा स्टेशन: ट्रेन संख्या 17005/17006, हैदराबाद—रक्सौल एक्सप्रेस तथा ट्रेन संख्या 15561/15562, दरभंगा—गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस।
बैरगनिया स्टेशन: ट्रेन संख्या 17433/17434



तिरुपति—रक्सौल एक्सप्रेस।

रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार, इन ट्रेनों का ठहराव प्रायोगिक आधार

पर जल्द ही शुरू किया जाएगा। हालांकि, ठहराव लागू होने की निर्धारित तिथि की आधिकारिक

घोषणा अभी की जानी है। रेलवे प्रशासन ने संबंधित स्टेशन अधीक्षकों को टिकट बिक्री के आंकड़ों पर लगातार नजर रखने तथा यात्रियों के बीच इन सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है। टिकट बिक्री और यात्रियों की प्रतिक्रिया के आधार पर भविष्य में इन ठहरावों को स्थायी किए जाने की संभावना रहेगी।

वर्षों की मांग और सामाजिक पहलु लाई रंग- घोड़ासहन, रीणा और बैरगनिया क्षेत्र के लोग लंबे समय से लंबी दूरी की प्रमुख ट्रेनों के ठहराव की मांग कर रहे थे। सीमावर्ती इलाका होने के कारण यहां के यात्रियों को दूसरे राज्यों तक जाने के लिए अक्सर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती थी।

ऐसे में रेलवे बोर्ड का यह निर्णय क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता पुरुषोत्तम चौधरी ने रेलवे बोर्ड और वरिष्ठ रेल अधिकारियों को पत्र लिखकर इन स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव की आवश्यकता और उपयोगिता से अवगत कराया था। इसके बाद तकनीकी एवं परिचालन संबंधी व्यवहार्यता की जांच के उपरांत रेलवे बोर्ड ने ठहराव को मंजूरी प्रदान की। रेलवे के इस फैसले से स्थानीय लोगों, व्यापारियों और दैनिक यात्रियों में खुशी का माहौल है। लोगों को उम्मीद है कि इन ट्रेनों के ठहराव से क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लंबी दूरी की यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक बनेगी।

1500 वर्ष पुरानी आस्था और परंपरा का प्रतीक

बीएनएम @ सहरसा

बिहार के सहरसा जिले के कहरा प्रखंड अंतर्गत दिवारी स्थित पां विषहरी मनसा देवी स्थान मिथिला और कोसी अंचल की अटुट आस्था एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख केंद्र है। सहरसा मुख्यालय से लगभग पांच से छह किलोमीटर दक्षिण सहरसा-सिमरी बखियापुर मार्ग पर स्थित यह सिद्धपीठ धार्मिक श्रद्धा के साथ अपनी अनूठी सामाजिक परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इस मंदिर का इतिहास करीब 1500 वर्ष पुराना है। लोककथाओं के अनुसार, मां विषहरी अपने अनन्य भक्त, बर्नागांव निवासी विश्वनाथ झा के पुत्र के कंधे पर सवार होकर भागलपुर क्षेत्र से यहां पहुंची थीं और इसी स्थान को अपना निवास बनाया। बताया जाता है कि दरभंगा राज के अधीन राजबनेली रियासत के राजाओं ने मंदिर के रखरखाव के लिए 51 बीघा भूमि दान में दी थी, जिसमें आठ बीघा भूमि पर मूल मंदिर परिसर का विस्तार हुआ। इस मंदिर की मान्यताएं प्रसिद्ध बिहुला-विषहरी लोककथा



से भी जुड़ी हैं। कहा जाता है कि चांदों सौदागर द्वारा मां विषहरी की पूजा से इनकार करने पर

उनके पुत्र बाला लखेंद्र को सर्प ने डस लिया था। इसके बाद उनकी पत्नी बिहुला ने अपनी अटुट भक्ति से पति के प्राण वापस प्राप्त किए। इस लोककथा का प्रभाव आज भी कोसी और अंग क्षेत्र की धार्मिक परंपराओं में दिखाई देता है। दिवारी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां सदियों से नाई समाज के लोग वंशानुगत रूप से मुख्य पुजारी की भूमिका निभाते आ रहे हैं। समाज के दो दर्जन से अधिक परिवार माता की सेवा और श्रद्धालुओं को पूजा कराने में लगे हैं। यह परंपरा सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल मानी जाती है। मंदिर में पांच बहन भगवती के रूप में माता धुताला, माता मनसा, माता मिसड़ा, माता विषहरी और माता पायल की पूजा की जाती है। श्रद्धालु गर्भगृह में पिंडी स्वरूप में विराजमान भगवती की पूजा-अर्चना करते हैं। इस दौरान कच्चा दूध, धान का लावा, बताशा, लड्डू, पान, अक्षत, फूल, सुपारी और लाल चुनरी अर्पित की जाती है। स्थानीय लोगों के बीच मंदिर के पवित्र जल, जिसे नीर कहा जाता है, को लेकर भी विशेष आस्था है।

स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक उपयोग से बचने की अपील

बीएनएम @ बगहा / पश्चिम चंपारण

नगर परिषद बगहा में स्वच्छता ही सेवा-2026

अभियान के तहत स्वच्छता साथियों ने अनुमंडल परिसर, मैदान और मंदिर परिसर में साफ-सफाई



की। इस दौरान होटल और रेस्तराेंट संचालकों को प्रतिबंधित प्लास्टिक व पॉलीथिन का उपयोग नहीं करने तथा पर्यावरण-अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए जागरूक किया गया। नगर कार्यपालक पदाधिकारी सरोज

कुमार बैठा ने कहा कि स्वच्छता सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। वहीं, स्वच्छता पदाधिकारी अब्दुल बाकी ने लोगों से कचरा इधर-उधर नहीं फेंकने और प्लास्टिक के उपयोग से बचने की अपील की। नगर परिषद ने नागरिकों, व्यवसायियों और संस्थानों से अभियान में सहयोग कर स्वच्छ एवं सुंदर बगहा बनाने का आह्वान किया।

दिल्ली में लोकतंत्र बनाम सुरक्षा का महासंग्राम! जंतर- मंतर बना सत्ता की अग्निपरीक्षा!

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

दिल्ली में लोकतंत्र पर पहरा या सुरक्षा का चक्रव्यूह ? - 57 मेट्रो स्टेशन बंद,ट्रेनें रद्द और सुप्रिम कोर्ट तक पहुंचा सियासी संग्राम! लोकतंत्र की आवाज या कानून-व्यवस्था की चुनौती ? - दिल्ली में 57 मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदी,अनेक मेल एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द -आखिर किस बात का है इतना डर? लोकतंत्र पर तीखी बहस !खड़े किए बड़े सवाल ? वैश्विक स्तरपर 9 अक्टूबर 2026 मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं को लेकर 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित कांक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन ने राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक, प्रशासनिक और संवैधानिक बसस तेज सर दी है।प्रदर्शन से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने, दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशनों पर पाबंदियों की तैयारी

सवाल मतदाता का है, जवाबदेही सरकार और चुनाव आयोग की भी है

सौरभ वाणेश

आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन-सा राजनीतिक दल किसके पक्ष में खड़ा है, बल्कि सवाल यह है कि मतदाता के मन में उठ रहे संदेहों का समाधान कौन करता? लोकतंत्र की असली ताकत सत्ता के प्रचार में नहीं, बल्कि जनता के विश्वास में होती है। जब मतदाता सूची, चुनाव प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर तरह-तरह के सवाल उठने लगें और उनके जवाब स्पष्ट तथा समय पर जनता के सामने न आएँ, तो भ्रम की स्थिति पैदा होना स्वाभाविक है। यह स्थिति किसी एक दल या एक विचारधारा तक सीमित नहीं है। आज सत्ता पक्ष के पास अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए तमाम साधन हैं। सरकार अपनी योजनाओं, उपलब्धियों और नीतियों का प्रचार पूरे जोर-शोर से करती है। यह उसका अधिकार है। लेकिन लोकतंत्र में केवल सरकार की बात जनता तक पहुंचना पर्याप्त नहीं है। सरकार के निर्णयों पर सवाल उठाने वाले नागरिकों, राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों को भी अपनी बात रखने का समान अवसर मिलना चाहिए और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। निर्वाचन आयोग स्वयं मतदाता सेवाओं के लिए नाम खोजने, मतदाता सूची में संशोधन, शिकायत दर्ज करने और अपील कीथी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। वर्तमान में आयोग के पोटैल पर एसआइआर 2026 से संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध हैं। आयोग का घोषित उद्देश्य यह है कि कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई अप्राप्त व्यक्ति उसमें शामिल न हो। फिर सवाल यह है कि यदि व्यवस्था इतनी स्पष्ट है तो मतदाता के बीच भ्रम की गुंजाइश क्यों पैदा हो रही है? यही वह प्रश्न है जिसका जवाब केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं दिया जा सकता। आज चुनाव आयोग को लेकर असह-अलग राजनीतिक दलों और समूहों की ओर से अनेक दावे किए जा रहे हैं। इनमें से कौन-सा दावा तथ्यात्मक है और कौन-सा राजनीतिक आरोप— इसका फैसला जनता को प्रमाण और आधिकारिक जानकारी के आधार पर करना चाहिए। लेकिन यहां सरकार और निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। यदि किसी चुनावी प्रक्रिया को लेकर जनता के मन में

और दिल्ली पहुंचने वाली कुछ मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने के फैसलों ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं?।क्या यह कदम कानून- व्यवस्था बनाए रखने की एहतियाती रणनीति है या इसका असर नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार पर भी पड़ रहा है? यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोदिया महाराष्ट्र मीडिया के हवाले से बातना चाहूंगा कि यहाँ 57 मेट्रो स्टेशन और रेल सेवाओं पर पाबंदी से बढ़ा विवाद, रेलवे बोर्ड के 9 अक्टूबर के आदेशके अनुसार निर्धारित समयावधि में नई दिल्ली और हजमत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कुछ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को उनके शुरुआती स्टेशनों से रद्द किया गया है।ये पाबंदियां 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच पहुंचने वाली संबंधित ट्रेनों पर लागू बताई गई हैं। दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रखने की व्यवस्था की घोषणा की है।उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पाबंदियों का प्रभाव रेंड, येलो, ब्लू, वायलेट,पिंक और मैजेंटा लाइनों सहित कई मेट्रो मार्गों पर पड़ना है। इससे यात्रियों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और दूसरे जरूरी कामों से दिल्ली आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी हो सकतीहै।हालांकि सभी ट्रेनों के रद्द होने या पूरी मेट्रो सेवा बंद होने का दावा करना सही नहीं होगा पाबंदियों का वास्तविक दायरा संबंधित आधिकारिक आदेशों से ही स्पष्ट होगा। साथियों बात अगर हम सीजेपी का ऐलान युवाओं से डरती है सरकार तो पूरा देश बंद कर दे को समझने की करें तो, सीजेपी के संस्थापक ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि जंतर- मंतर निर्धारित प्रदर्शन स्थल है और पार्टी हर हाल में प्रदर्शन करेगी। उनका तर्क है कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकार

है और कथित चुनावी अनियमितताओं पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया है, जबकि जंतर-मंतर और आसपास की इलाकों में पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। पार्टी ने देशभर में अपने कम से कम 10 हजार सदस्यों को हिरासत में लिए जाने का दावा भी किया है, लेकिन इस संख्या की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस दावे को स्थापित तथ्य के बजाय पार्टी के आरोप के रूप में ही सटीकता से देखा जाना चाहिए। साथियों बात अगर हम सुप्रीम कोर्ट में उठा सवाल सुरक्षा या नागरिक अधिकार? इसको समझने की करें तोअब इस विवाद ने न्यायिक स्तर पर भी ध्यान खींचा है।वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रदर्शन से पहले रेल सेवाओं, मेट्रो स्टेशनों तथा इंटरनेट सेवाओं पर संभावित पाबंदियों को लेकर चिंता जताई।सिब्बल ने सवाल उठाया कि शांतिपूर्ण

प्रदर्शन के लिए राजधानी आने वाले लोगों की आवाजाही पर इतनी व्यापक रोक क्यों लगाई जा रही है। दूसरी ओर, प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस को खुली छूट देने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने युवाओं के भविष्य और उनके परिवारों पर कानूनी कार्रवाई के प्रभाव को ध्यान में रखने की बात कही। साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया कि आदतन अपराधियों या गंभीर अपराधों के आरोपियों को पूर्व आदेशों के तहत मिली सुरक्षा का लाभ स्वतः नहीं मिलेगा। न्यायालय की इस टिप्पणी का अर्थ कानून-व्यवस्था की आवश्यकता को नकारना नहीं,बल्कि कार्रवाई में सटीकता से उचित संतुलन बनाए रखना है। साथियों बात अगर हम अघोषित आपातकाल का आरोप और 1942 के आंदोलन से तुलना को समझने की करें तो, ऑल इंडिया स्टूटेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वीडियो

संदेश में गिरफ्तारियों,दिल्ली आने से रोकें जाने और परिवहन प्रतिबंधों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इन परिस्थितियों की तुलना 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से करते हुए इसे अघोषित आपातकाल करार दिया। यह उनका राजनीतिक आरोप सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने युवाओं से लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन जारी रखने की अपील की है। दूसरी ओर, प्रशासन के सामने संभावित भीड़, कि आदतन अपराधियों या गंभीर अपराधों के आरोपियों को पूर्व आदेशों के तहत मिली सुरक्षा का लाभ स्वतः नहीं मिलेगा। न्यायालय की इस टिप्पणी का अर्थ कानून-व्यवस्था की आवश्यकता को नकारना नहीं,बल्कि कार्रवाई में सटीकता से उचित संतुलन बनाए रखना है।

लोकतंत्र की असली परीक्षा: विरोध का अधिकार और व्यवस्था की सटीकता से जिम्मेदारी है। साथियों बात अगर इस पूरे घटनाक्रम का महत्व किसी एक पार्टी या एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं है इसको समझने की

करें तो, चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो उनका पारदर्शी और तथ्याधारित जवाब देना संस्थाओं की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है। उसी तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की रक्षा करना भी लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। प्रशासन को सुरक्षा संबंधी कदम उठाने का अधिकार है, लेकिन उनकी आवश्यकता, अनुपात और नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा भी जरूरी है। दूसरी ओर, प्रदर्शनकारियों को कानून का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन करें इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि 10 अक्टूबर का घटनाक्रम इस बात की कसौटी बनेगा कि लोकतंत्र में असहमति को किस तरह संभाला जाता है। (—लेखक ऋतु विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) हैं)

बेटियों को बचपन, अधिकार और उड़ान देने का समय

किसी समाज की प्रगति का वास्तविक आकलन उसकी ऊंची इमारतों, आर्थिक समृद्धि अथवा तकनीकी उपलब्धियों से ही नहीं, इस बात से भी होता है कि वहां जन्म लेने वाली प्रत्येक लड़की को अपने अपने चुनने, उन्हें पूरा करने और अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने की कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है। विंडबना है कि 21वीं सदी में विज्ञान और तकनीक नई ऊंचाइयों छू रहे हैं, महिलाएं अंतरिक्ष से लेकर संसद तक अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं लेकिन दुनिया के अनेक हिस्सों में लाखों लड़कियों का बचपन आज भी बाल विवाह जैसी कुप्रथा की भेंट चढ़ रहा है। उनके हाथों में किताबों के बजाय घरेलू जिम्मेदारियों थमा दी जाती हैं और उनके सपनों को सामाजिक परंपराओं की दुहाई देकर समय से पहले कुचल दिया जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं बल्कि उस व्यवस्था से सवाल करने का दिन है, जो लड़की के जन्म से ही उसके भविष्य की सीमाएं निर्धारित करने लगती हैं। प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2011 को प्रस्ताव 66/170 के माध्यम से की थी। वर्ष 2012 में पहली बार इस दिवस का आयोजन हुआ। वर्ष 2026 का विषय है ‘बाल विवाह समाप्त करो और लड़कियों के अधिकारों में निवेश करो।' यह संदेश स्पष्ट करता है कि बालिकाओं के सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान केवल कानून बनाने अथवा जागरूकता अभियान चलाने से नहीं होगा। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, कौशल विकास और आर्थिक स्वतंत्रता में निरंतर निवेश करना होगा। संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ ने इस वर्ष लड़कियों की आवाज, नेतृत्व तथा अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने के अधिकार को विशेष महत्व दिया है। बाल विवाह वस्तुतः बचपन, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता का एक साथ हनन है। कम उम्र में विवाह होने से लड़कियों की पढ़ाई छूटने, कम उम्र में गर्भधारण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं, घरेलू हिंसा और आर्थिक निर्भरता का जोखिम बढ़ सकता है। इससे उनका व्यक्तिव विकास बाधित होता है और निर्णय लेने की क्षमता सीमित रह जाती है। गरीबी, दहेज की चिंता, असुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा की गलत धारणाएं और पितृसत्तात्मक मानसिकता इस कुप्रथा को बनाए रखने में भूमिका निभाती हैं। कई

श्वेता गोयल



परिवार आर्थिक कठिनाइयों से छुटकारा पाने अथवा लड़की को सुरक्षा सुनिश्चित करने के नाम पर कम उम्र में विवाह को उचित ठहराते हैं जबकि वास्तविक समाधान उसे शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, दुनिया में हर वर्ष 1.2 करोड़ से अधिक लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो जाता है। यह आंकड़ा बताता है कि बाल विवाह कोई सीमित क्षेत्र की सामाजिक समस्या नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर बाल अधिकारों के सामने खड़ी गंभीर चुनौती है। यूनिसेफ के अनुसार, पिछले दशकों में बाल विवाह की व्यापकता घटने में प्रगति हुई है लेकिन इसकी रफ्तार तेज करना जरूरी है। संघर्षग्रस्त क्षेत्रों, मानवीय संकटों और जलवायु आपदाओं से प्रभावित समुदायों में लड़कियों के सामने जोखिम और बढ़ जाते हैं। विस्थापन, गरीबी तथा शिक्षा और सुरक्षा सेवाओं की अनुपलब्धता उन्हें कम उम्र में विवाह के प्रति अधिक असुरक्षित बना सकती है। भारत में भी स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के अनुसार, 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग की 23.3 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हो गया था। यह आंकड़ा पिछले सर्वेक्षण के 26.8 प्रतिशत से कम अवश्य है लेकिन अब भी लगभग हर चार में से एक महिला के बाल विवाह के अनुभवों और संकेत करता है। राज्यों और सामाजिक समूहों के बीच अंतर भी इस चुनौती को जटिल बनाता है। इसलिए राष्ट्रीय ओसट में सुधार को समरथा का अंत मान लेना उचित नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों, वंचित समुदायों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक प्रभावी सहायता पहुंचाना अभा भी आवश्यक है।

बाल विवाह के विरुद्ध भारत में कानूनी व्यवस्था मौजूद है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सामान्यतः लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष से कम आयु में विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। कानून का उद्देश्य केवल विवाह रोकना नहीं बल्कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना भी है। हालांकि, कानून

की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बाल विवाह की सूचना मिलने पर प्रशासन कितनी तत्परता से कार्रवाई करता है, बाल संरक्षण तंत्र कितना सक्रिय है और पीड़ित बालिका को विवाह रकने के बाद शिक्षा, परामर्श, सुरक्षा तथा आर्थिक सहायता कितनी उपलब्ध होती है। किसी विवाह को रोक देना महत्वपूर्ण है लेकिन लड़की को उसके बाद सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन का अवसर देना उतना ही जरूरी है।

बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए भारत में कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान ने बालिका के जन्म, शिक्षा और सामाजिक सम्मान को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाने में भूमिका निभाई है। सुकन्या समृद्धि योजना परिवारों को बालिका के भविष्य के लिए बचत करने का अवसर देती है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्तियां, विद्यालयों में शौचालय, किशोरियों के स्वास्थ्य कार्यक्रम और कौशल विकास की पहलें उनकी निरंतर पढ़ाई तथा आत्मनिर्भरता के लिए उपयोगी हैं। परिसम बालाल की कन्याश्री जैसी योजनाओं ने बालिकाओं की शिक्षा जारी रखने और बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया है। किंतु योजनाओं की वास्तविक उपलब्धि घोषणाओं अथवा लाभाभित्थियों की संख्या से नहीं, इस बात से मापी जानी चाहिए कि कितनी लड़कियां विद्यालय में बनी रही, कितनों का विवाह कानूनी आयु से पहले नहीं हुआ और कितनों को अपनी पसंद का जीवन चुनने की स्वतंत्रता मिली। बालिका अधिकारों का प्रश्न शिक्षा और विवाह की आयु तक सीमित नहीं है। डिजिटल युग में इंटरनेट तक असमान पहुंच, ऑनलाइन उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव और सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों की कमी भी लड़कियों की संभावनाओं को सीमित करती हैं। विद्यालयों में विज्ञान, तकनीक, गणित और उद्यमिता के अवसरों के साथ जीवन-कौशल, डिजिटल साक्षरता, आत्मरक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किशोरियों को मासिक धर्म, प्रजनन स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर बिना संकोच बात करने का वातावरण मिलना चाहिए। परिवारों को भी यह

समझना होगा कि सुरक्षा के नाम पर लड़कियों की आवाजाही, मित्रता और शिक्षा पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाना समाधान नहीं है। सुरक्षित वातावरण तैयार करना समाज और संस्थाओं की जिम्मेदारी है।

वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता की स्थिति भी बताती है कि अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। विश्व आर्थिक मंच की ‘ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025’ में भारत 148 अर्थव्यवस्थाओं में 131वें स्थान पर रहा और उसका समग्र लैंगिक समानता स्कोर 64.4 प्रतिशत दर्ज किया गया। यह सूचकांक बालिकाओं की स्थिति का प्रत्यक्ष माप नहीं है लेकिन व्यापक लैंगिक असमानताओं की ओर संकेत करता है, जिनका प्रभाव लड़कियों के अवसरों और भविष्य पर पड़ सकता है। इसी प्रकार, संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन और अंतर-संसदीय संघ की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, 1 जनवरी 2025 तक विश्वभर में मॉन्रमंडल स्तर के पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 22.9 प्रतिशत थी। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा और प्रतिभा के बावजूद निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता बनी हुई है। बाल विवाह समाप्त करने के लिए सरकार, प्रशासन, विद्यालयों, पंचायतों, धार्मिक-सामाजिक संगठनों और परिवारों को साझा जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रत्येक बालिका का विद्यालय में नामांकन ही नहीं, उसकी नियमित उपस्थिति और माध्यमिक शिक्षा पूरी करना भी सुनिश्चित किया जाए। बाल विवाह की आशंका वाले क्षेत्रों में स्थानीय निगरानी समिधियां सक्रिय हों, शिकायत तंत्र सुलभ बने और पीड़ित लड़कियों को संरक्षण तथा पुनर्वास मिले। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ऐसी सहायता दी जाए, जिससे बेटी की पढ़ाई आर्थिक बोझ न बने। योजनाओं के बजट, लाभाभित्थियों और परिणामों का सार्वजनिक मूल्यांकन हो तथा बालिकाओं को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सबसे बढ़कर, लड़कों और पुरुषों को भी समानता के इस अभियान का सहभागी बनाना होगा क्योंकि भेदभावपूर्ण सामाजिक मान्यताओं में बदलाव सामूहिक प्रयास से ही संभव है। किसी लड़की का भविष्य उसकी जन्मतिथि, आर्थिक स्थिति या सामाजिक रुढ़ियों से निर्धारित नहीं होना चाहिए। (लेखिका 18 वर्ष से अधिक समय से शिक्षण क्षेत्र में सक्रिय शिक्षाविद है)

(यह लेखिका के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

शेयर बाजार में शनि राहु और केतु की छाया?

सनत जैन

भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के लिए गुरुवार का दिन बहुत खराब साबित हुआ। एक ही झटके में 11.37 लाख रुपए निवेशकों के डूब गए। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। सभी सेक्टर के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। शेयर बाजार 1045 अंक गिरकर मुंबई स्ट्याक एक्सचेंज 71593 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्ट्याक एक्सचेंज 371 अंक की गिरावट के साथ 22232 पर बंद हुआ। रही सही कसर डॉलर के मुकाबले रुपया ने लगभग 97 रुपए के स्तर पर पहुंचकर पूरी कर

दी। पिछले दो सप्ताह से रिजर्व बैंक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत को संभालने के लिए काफी प्रयास कर रहा है। इसके बाद भी रुपया गिरने से रुक नहीं रहा है। रही सही कसर कच्चे तेल के दाम बढ़ने से डॉलर की मांग बढ़ती जा रही है, जिसके कारण डॉलर के मुकाबले रुपया में लगातार गिरावट देखी जा रही है। कच्चे तेल और डॉलर का भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। जैसे-जैसे डॉलर के रेट रुपए के मुकाबले बढ़ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को उठाना पड़ रहा है।

आखिर शेयर बाजार की यह हालत क्यों हुई, इसको लेकर तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं। रिजर्व



बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में रेपो रेट में बदलाव किया है। रेपो रेट 0.25 आधार अंक बढ़कर 5.50 की गई है। इसको लेकर शेयर मार्केट में घबराहट देखने को मिल रही है। वैश्विक देशों के शेयर बाजारों में भी इन दिनों भारी उथल-पुथल मची हुई है। जिसका असर भारतीय शेयर बाजार में दिख रहा है। सबसे

बड़ी चिंता की बात यह है, भारत के शेयर बाजार से विदेशी निवेश लगातार निकलता चला जा रहा है, जिसके कारण डोमेस्टिक निवेशकों भी घबराहट में आ गए हैं। भारत की वित्तीय संस्थाओं के ऊपर भी भारी दबाव देखने को मिल रहा है। इससे भारत का शेयर बाजार निरर्थक रूप में सुधर पायेगा? इसको

लेकर तरह-तरह की चिंता व्यक्त की जाने लगी है। रही सही कसर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दादा ने पूरी कर दी है। ट्रंप ने एक नया फरमान जारी किया है। जिसमें भारत की 8 आईटी कंपनियों को पीईआरएफ प्रोग्राम से बाहर किया है। इनमें इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉमिनजेंट, कैपजोमिनी सहित आठ कंपनियों के कर्मचारियों को अमेरिकी ग्रीन कार्ड प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। इनमें माइक्रोसॉफ्ट और एडोब भी शामिल है। इसका असर भारतीय कंपनियों में पडना रहा है। ट्रंप के इस कदम से भारतीय आईटी कंपनियों को अमेरिका में काम मिलने से दिक्कत होगी, जिसका प्रभाव इन कंपनियों पर पडना तय है। पिछले 2 साल

से भारतीय शेयर बाजार की हालत खस्ता है। शेयर बाजार को संभालने के लिए जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, अब सब उल्टे पड रहे हैं। ऐसा लगता है, ग्रह नक्षत्र ने जो दशा बदली है। इसका सबसे बड़ा असर शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है।

शेयर बाजार और भारतीय राजनीति में इन दिनों कब कौन सा परिवर्तन हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरह की चिंता अर्थशास्त्री व्यक्त कर रहे हैं, वह विचारणीय है। उनका कहना है, भारत में इतने बड़े आर्थिक संकट के दौर में अच्छे अर्थशास्त्रियों का नहीं होना, सरकार द्वारा स्वयं निर्णय लेना।

आज का राशिफल



मे़ष राशि: आज जो भी काम शुरू करेंगे वो समय पर पूरा हो जाएगा। आपको करियर से संबंधित नए अवसर मिलेंगे। नए व्यापार को शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। कॉमर्स के विद्यार्थी आज मार्केटिंग को समझने के लिए शिक्षकों की सहायता लेंगे, जो आपके भविष्य में बेहद काम आएंगी। आज आप अपनी मेहनत, धैर्य और समझदारी से सारे काम निपटा लेंगे। शुभ अंक – 8

वृष राशि: ऑफिस के लोगों में आपका रुतबा बनेगा। किसी विशेष व्यक्ति से आज आपकी बात हो सकती है। आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा, धन के नए स्रोत प्राप्त होंगे। आज अपना व्यवहार लचीला रखें और दूसरों की बातें समझने का प्रयत्न करें। छोटे बच्चे बहुत खुश रहेंगे, वे अपने लिए कोई नया खेल तलाश करेंगे। शुभ अंक – 6

मिथुन राशि: आज का दिन मिली जुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। आज किसी रिश्तेदार से आपकी फोन पर बात होगी, जिससे आपको अच्छा महसूस होगा। दंपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। महिलाएं आज ऑनलाइन कोई नई हिंदी सीखने की कोशिश करेंगी। पिता का सहयोग आपके साथ रहेगा। लेखकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, उनके लेखन कार्यों की सराहना होगी। शुभ अंक – 2

कर्क राशि: आज आपको ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा, जिससे आपको मन प्रसन्न रहेगा। आज आप विदेश में भी व्यापार करने की योजना बनाएंगे। आपकी सोशल मीडिया पर किसी से बात हो सकती है, जिससे आपको भविष्य में बहुत फायदा होगा। आज बच्चे घर के काम में माता की मदद करेंगे। शुभ अंक – 9

सिंह राशि: काम के मामलों में आप बेहद व्यावहारिक रहेंगे। आपके मन में बहुत दिनों से कारोबार को लेकर कोई योजना चल रही है, तो आज आप उस योजना पर काम शुरू करेंगे, जिससे आपको कोई बड़ा लाभ मिलेगा। आज आपकी मीठी वाणी आपके काम को जल्दी पूरा करवाने में मदद करेगी। किसी बात को लेकर परेशान हैं तो आज आपकी टैशन खत्म होगी। शुभ अंक – 4

कन्या राशि: आपको दूसरों से प्रेरणा लेकर काम करने की जरूरत है। आज बोलने से ज्यादा आपको काम पर ध्यान देना चाहिए। आज आपको अपने माता पिता के साथ समय बिताना चाहिए। संयम और धैर्य के साथ ही आपको अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। किसी रिश्तेदार से चली आ रही अनबन आज खत्म हो जाएगी। शुभ अंक – 2

तुला राशि: अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, तो आपको उसे बढ़ाने के लिए थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। आज कोई पड़ोसी आपसे किसी प्रकार की सहायता मांगेगा, जिसे आप आसानी से पूरा करेंगे। लोगों के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा। किसी रिश्तेदार से आपकी फोन पर लंबी बात होगी। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। शुभ अंक – 3

वृश्चिक राशि: ऑफिस के किसी सहकर्मी के साथ बिजनेस मीटिंग में शामिल होंगे। आज अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपका मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहेगा। छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा, आप अपनी पढ़ाई को लेकर पूरी तरह सतर्क रहेंगे। आज की गई मेहनत का लाभ मिलेगा। शुभ अंक – 5

धनु राशि: धनु राशि वालों आज पूरा दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। लोगों का भरोसा आप पर बना रहेगा। आपकी ईमानदारी से लोग प्रेरणा लेंगे। महिलाएं घर के काम से जल्द ही राहत पा लेंगी। आज आप दोस्ती के साथ समय बिताएंगे। कई दिनों से रुका हुआ पैसा आज वापस मिलेगा। आप अपनी बातें अपने पिता से जरूर साझा करें, इससे जीवन में चल रही परेशानियों का हल मिलेगा। शुभ अंक – 6

मकर राशि: आज आप सोशल मीडिया के जरिए सामाजिक कार्यों में सहयोग देंगे। शिक्षकों की मदद से विद्यार्थियों का कोई प्रोजेक्ट पूरा होगा। किस्मत का साथ आपको आर्थिक लाभ दिलाएगा। पहले की गई मेहनत का आज दोगुना लाभ मिलेगा। आज कामकाज ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आपको खुद के लिए समय निकाल पाना मुश्किल होगा। शुभ अंक – 7

कुंभ राशि: आपके कोई कचहरी के मामले थोड़े रुक सकते हैं, लेकिन समय रहते सब ठीक हो जाएगा। आज आप जो भी व्यापार शुरू करेंगे, उसमें सफलता हासिल होगी। आज आपको किसी दोस्त का सहयोग मिलेगा।



आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रेनशाँ और हेजलवुड को फायदा, टी-20 में श्रेयस चौथे स्थान पर

एजेंसी, नई दिल्ली

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरबन टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू रेनशाँ और जोश हेजलवुड को आईसीसी की ताजा पुरुष टेस्ट खिलाड़ी रैंकिंग में फायदा हुआ है। भारत के श्रेयस अय्यर ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में करियर का सर्वश्रेष्ठ चौथा स्थान हासिल कर लिया है। आईसीसी के अनुसार डरबन टेस्ट की पहली पारी में 190 रन बनाने वाले रेनशाँ ने दूसरी पारी में भी 82 रन की अहम पारी खेली। उनके इस प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया को मैच में मजबूत स्थिति हासिल करने में मदद मिली। रेनशाँ टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष 100 से बाहर रहने के बाद संयुक्त रूप से 49वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन चार स्थान ऊपर चढ़कर 34वें स्थान पर पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के



सलामी बल्लेबाज एडेन मार्करम ने भी चार स्थान की छलांग लगाई और संयुक्त रूप से 10वें स्थान पर पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने डरबन टेस्ट के अंतिम दिन 49 रन देकर छह विकेट लिए थे। इस प्रदर्शन के बाद वह टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में दो स्थान ऊपर चढ़कर सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क गेंदबाजों की सूची में शीर्ष

पर बने हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नॉखिया तीन साल से अधिक समय बाद अपना पहला टेस्ट खेलने के बाद गेंदबाजी रैंकिंग में लौट आए हैं। वह 34वें स्थान पर हैं। भारत के रवींद्र जडेजा टेस्ट ऑलराउंडरों की रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के वियान मुल्लर एक स्थान ऊपर चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि साइमन हार्मर ने पांच

स्थान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 23वां स्थान हासिल किया है। अब्दु धाबी में अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला गया एकमात्र टेस्ट ड्रा समाप्त हुआ। इस मुकाबले के बाद अफगानिस्तान के रहमत शाह टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में 13 स्थान ऊपर चढ़कर 13वें स्थान पर पहुंच गए। बांग्लादेश के लिटन दास तीन स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 29वें स्थान पर हैं। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद ने इस मुकाबले में हैट्रिक लेने के साथ पांच विकेट हासिल किए। इसके बाद वह टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में सात स्थान ऊपर चढ़कर 38वें स्थान पर पहुंच गए। ताजा पुरुष टी-20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारत के श्रेयस अय्यर ने करियर का सर्वश्रेष्ठ चौथा स्थान हासिल किया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की घरेलू श्रृंखला के शुरुआती मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने तीन स्थान की छलांग लगाई।

टी20 में गेल जैसी क्षमता रखते हैं अभिषेक, लंबे समय तक याद रखा जाएगा उनका नाम : चेतेश्वर पुजारा

एजेंसी, नई दिल्ली

पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा का मानना है कि अभिषेक शर्मा में वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल जैसी क्षमता है और टी20 क्रिकेट में उनके प्रदर्शन को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 श्रृंखला के चौथे मुकाबले से पहले पुजारा ने जियोहॉटस्टार के कार्यक्रम 'गैम प्लान' में अभिषेक की शानदार बल्लेबाजी, ईशान किशन की भूमिका और नमन धीर की गेंदबाजी पर अपनी राय रखी।

भारत ने इंदौर में तीसरा टी20 मुकाबला जीतकर श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। अब टीम की



नजरें हैदराबाद में होने वाले चौथे मुकाबले को जीतकर श्रृंखला अपने नाम करने पर हैं। अभिषेक शर्मा के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2,000 रन पूरे करने पर पुजारा ने कहा, “किसी ने नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी इतने बड़े मुकाम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अभिषेक ने

जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि वह अब तक भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ियों में से एक हैं। उनका नाम लंबे समय तक याद रखा जाएगा।” उन्होंने कहा, “जब हम टी20 प्रारूप की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में तुरंत वेस्टइंडीज के क्रिस गेल का नाम

आता है। अभिषेक में भी उसी तरह की क्षमता है। इंदौर में उन्होंने जिस तरह परिपक्वता दिखाई और थोड़ा समय लेकर बल्लेबाजी की, वह महत्वपूर्ण है। उनके लिए पांच-छह गेंदें भी काफी समय होती हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि वह अपने खेल को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, विपक्षी टीम की ताकत को पहचान रहे हैं और उसी के अनुसार बल्लेबाजी कर रहे हैं।” पुजारा ने कहा कि हैदराबाद में अभिषेक के लिए घरेलू मैदान जैसा अनुभव भी फायदेमंद हो सकता है। उन्होंने कहा, “उन्होंने इस मैदान पर काफी क्रिकेट खेला है। टी20 में भी मैदान से परिचित होना और वहां खेलने का अनुभव मायने रखता है।”

चैंपियंस लीग : यामल के शानदार प्रदर्शन से बार्सिलोना की वापसी, गालतासराय को 4-1 से हराया

एजेंसी, इस्तांबुल

स्टार खिलाड़ी लामिन यामल के शानदार प्रदर्शन की बदौलत बार्सिलोना ने मंगलवार को यूईएफए चैंपियंस लीग 2026-27 में गालतासराय को 4-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। मंगलवार को इस्तांबुल के राम्स पार्क में खेले गए मुकाबले में बार्सिलोना ने एक गोल से पिछड़ने के बाद दमदार वापसी की। यामल ने दो गोल में सहायता की और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ बार्सिलोना अंक तालिका में आसलन और स्पॉर्टिंग लिस्बन के साथ शीर्ष स्थान पर पहुंच गया।



तीनों टीमों ने अब तक अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। वहीं, तुर्किये का दिग्गज क्लब गालतासराय बिना अंक के तालिका में निचले स्थानों पर बना हुआ है। मुकाबले के शुरुआती दौर में बार्सिलोना ने गंद पर नियंत्रण

रखते हुए कई हमले किए, लेकिन पहला गोल गालतासराय ने किया। रूस के अलेक्सी बातराकोव के प्रयास पर जोआओ कैसेलो से गेंद लगकर दिखा बदल गई और गोल में चली गई। इस तरह मेजबान टीम ने बढ़त बना ली। पहले हाफ के समाप्त होने से ठीक पहले कैसेलो ने डैनी ओल्मो के पास को गोल में बदलकर बार्सिलोना को बराबरी दिला दी। दोनों टीमों मध्यांतर तक 1-1 की बराबरी पर थीं। दूसरे हाफ में यामल ने बार्सिलोना के आक्रमण को नई धार दी। उन्होंने फर्मिन लोपेज को शानदार पास देकर गोल करने में मदद की और बार्सिलोना को 2-1 की बढ़त दिला दी।

मैनचेस्टर यूनाइटेड के फुटबॉल प्रमुख पर बरसे मार्टिनेज, बोले-टीम को मजबूत बनाने के और प्रयास होने चाहिए थे

एजेंसी, मैड्रिड। मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर लिस्मांद्रो मार्टिनेज ने एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ चैंपियंस लीग में 0-2 की हार के बाद क्लब के शीर्ष प्रबंधन और खिलाड़ियों की भर्ती को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि चैंपियंस लीग में वापसी के बाद क्लब को टीम को मजबूत बनाने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए थे। मार्टिनेज ने यह बात मैच के बाद अमेजन प्राइम को दिए साक्षात्कार में कही। मार्टिनेज की इस टिप्पणी से मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। टीम सभी प्रतियोगिताओं में लगातार पांच मैचों से जीत हासिल नहीं कर पाई है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी उसने अब तक केवल एक जीत दर्ज की है और अंक तालिका में 13वें स्थान पर है। मार्टिनेज ने अमेजन प्राइम से कहा, “मुझे खुद पर काफी निभंत्रण रखना पड़ता है। लेकिन कभी-कभी यह हमारे क्लब की मौजूदा स्थिति का आईना होता है। हमने पिछले सत्र में शानदार प्रदर्शन किया था। अब हम शीर्ष स्तर के प्रबंधन से, ऊपर बैठे लोगों से, और अधिक उम्मीद करते हैं कि वे प्रतिस्पर्धा करने के लिए और खिलाड़ी लेकर आएंगे, क्योंकि कई अन्य टीमों भी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को ला रही हैं।

बिजनेस

भारत-अमेरिका संबंध ‘काफी अच्छे’, कोई समस्या नहीं: गोयल

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत तथा अमेरिका के संबंध “काफी अच्छे” हैं और राजनीतिक विचारधारा में बदलाव के बावजूद इनमें और सुधार ही होगा।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2026 को संबोधित करते हुए यह बात कही। गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें रक्षा, प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिजों और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा, “बेशक, हमारे संबंध पहले से ही काफी अच्छे हैं। गोयल ने कहा कि मुझे अब भी कोई समस्या नहीं दिखती। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि येग मानना है कि भारत तथा अमेरिका के संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं और दुनिया के लिए इनके दूरगामी मायने हैं, क्योंकि दोनों



बड़े लोकतंत्र हैं।” केंद्रीय वाणिज्य मंत्री इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पद छोड़ने के बाद भारत-अमेरिका संबंधों में सुधार होगा। उन्होंने कहा, “यह ध्यान रखना चाहिए कि बात सिर्फ व्यापार की नहीं है। बेशक, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में भी वह ऐसा बना रहेगा। कुल मिलाकर,

मुझे अमेरिका के साथ किसी समझौते को लेकर भी कोई समस्या नहीं दिखती।” गोयल ने कहा, “ये व्यापार, रक्षा साझेदारी, प्रौद्योगिकी साझेदारी, महत्वपूर्ण खनिजों की साझेदारी और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क से जुड़ा मामला भी है।” उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बेहद करीबी संबंध बने हुए हैं। दोनों पक्ष रक्षा अय्यासों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी, वस्तुओं एवं सेवाओं की

आपूर्ति श्रृंखलाओं को खुला रखने जैसे क्षेत्रों में लगातार सहयोग कर रहे हैं। वाणिज्य मंत्री की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं, जब दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत कर रहे हैं।

इस समझौते की रूपरेखा की घोषणा फरवरी में की गई थी, लेकिन अमेरिका में शुल्क व्यवस्था में बदलाव के कारण बातचीत आगे भी जारी है। भारत चाहता है कि अमेरिकी बाजार में उसके सामान पर प्रतिस्पर्धी शर्तों की तुलना में कम शुल्क लगे। उल्लेखनीय है कि ऊंचे शुल्क के बावजूद वित्त वर्ष 2025-26 में अमेरिका को भारत का निर्यात मामूली 0.92 फीसदी बढ़कर 87.3 अरब डॉलर हो गया। वहीं, इस दौरान आयात 15.95 फीसदी बढ़कर 52.9 अरब डॉलर रहा। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का व्यापार अधिशेष घटकर 34.4 अरब डॉलर रह गया, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 40.89 अरब डॉलर रहा था।

नवरात्रि से दीपावली तक देश में 7 लाख करोड़ से अधिक के कारोबार का अनुमान : कैट

एजेंसी, नई दिल्ली

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने बुधवार को कहा कि इस वर्ष नवरात्रि से दीपावली तक देशभर में 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक का त्योहारी कारोबार होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के रिकॉर्ड कारोबार की तुलना में लगभग 15-18 फीसदी अधिक हो सकता है। नवरात्रि तथा दुर्गा पूजा के बाद, दशहरा, कर्वा चौथ, धनतेरस,दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती एवं तुलसी विवाह त्यौहार बड़े रूप में देश भर में मनाये जाते हैं।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं चांदनी चौक से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि ये प्रारंभिक अनुमान देशभर के विभिन्न राज्यों के प्रमुख व्यापारिक संगठनों एवं बाजारों से प्राप्त फीडबैक, उपभोक्ता मांग, त्योहारी खरीदारी के रुझान, ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी बाजारों की सक्रियता, स्थानीय उत्पादों की बढ़ती मांग तथा विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली व्यापक आर्थिक गतिविधियों



को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि पिछले वर्ष दीपावली के अवसर पर देशभर में लगभग 6.05 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड व्यापार हुआ था, जिसमें लगभग 5.40 लाख करोड़ रुपये का वस्तु व्यापार तथा 65,000 करोड़ रुपये का सेवा क्षेत्र शामिल था। इस वर्ष त्योहारी गतिविधियों से दीपावली तक अनुमानित त्योहारी कारोबार के 7 लाख करोड़ से ऊपर जाने की संभावना है। कहा कि कैट के आकलन के अनुसार, नवरात्रि से दीपावली तक अनुमानित त्योहारी कारोबार में प्रमुख क्षेत्रों की हिस्सेदारी लगभग इस प्रकार रह सकती है जिसमें किराना एवं एफएमसीजी 12

फीसदी, सोना, चांदी एवं आभूषण, 10 फीसदी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल्स, 8 फीसदी, कंज्यूमर ड्यूरेबल वस्तुएं 7 फीसदी, रेडीमेड गार्मेंट्स 7 फीसदी, गिफ्ट आइटम्स 7 फीसदी, होम डेकोर 5 फीसदी, फर्नीचर एवं फर्निशिंग 5 फीसदी, मिठाई एवं नमकीन 5 फीसदी, टेक्सटाइल एवं फैब्रिक्स 4 फीसदी, पूजा सामग्री 3 फीसदी,फल एवं फ्रूट्स 3 फीसदी, बेकरी एवं कन्फेक्शनरी 3 फीसदी, फुटवियर 2 फीसदी, अन्य वस्तुएं एवं संबंधित कारोबार 19 फीसदी हो सकता है। प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि इस वर्ष त्योहारी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण

होगी। नवरात्रि से दीपावली के दौरान परिवहन, लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स डिलीवरी, पैकेजिंग, वेयरहाउसिंग, होटल, रेस्तरां, पर्यटन, कैटरिंग, टेंट एवं डेकोरेशन, लाइटिंग, इवेंट मैनेजमेंट, कैब एवं स्थानीय परिवहन सहित अनेक सेवाओं में भारी मांग रहने की संभावना है। पिछले वर्ष सेवा क्षेत्र में लगभग 65,000 करोड़ के कारोबार के मुकाबले इस वर्ष सेवा क्षेत्र में 20-25 फीसदी तक वृद्धि का प्रादंभिक अनुमान है। इसके आधार पर त्योहारी अवधि में सेवा क्षेत्र का कारोबार लगभग 80,000 करोड़ से एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी त्यौहारों के सीजन में अवैध पवों के दौरान देशभर में बड़ी संख्या में धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यावसायिक आयोजन भी होंगे जिनमें मॉकेंट उत्सव, रामलीला, दुर्गा पूजा पंडाल, गरबा एवं डांडिया, दिवाली मिलन एवं मेले, प्रदर्शनों, स्थानीय बाजार कार्यक्रम, सोलाघाटी एवं सामुदायिक समारोह, कॉर्पोरेट कार्यक्रम तथा पारिवारिक आयोजन भी बड़ी संख्या में होंगे।

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव जारी, सेंसेक्स और निफ्टी में सपाट कारोबार

एजेंसी, नई दिल्ली

हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का जारी है। हालांकि, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों और एचडीएफसी बैंक के शेयर की बिकवाली से सेंसेक्स और निफ्टी सपाट कारोबार कर रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 32.96 अंक की गिरावट के साथ 73,000.82 अंक पर रहा, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी 32.65 अंक टूटकर 22,688.75 अंक पर रहा। हालांकि, बाद में दोनों प्रमुख सूचकांकों ने शुरुआती गिरावट की



भरपाई कर ली। फिलहाल, बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 14.82 अंक यानी 0.020 फीसदी की गिरावट के साथ 73,048.60 अंक पर टूट कर रहा है। वहीं, निफ्टी 3.60 अंक यानी 0.016 फीसदी की गिरावट के साथ 22,718.35

के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक, इंफोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, टेक महिंद्रा, मार्सुति और एचडीएफसी बैंक के शेयर सबसे अधिक चढ़े। वहीं, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, लार्सन एंड टुबो, पावर ग्रिड और इटर्नल के शेयर में गिरावट रही। इसके अलावा एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉर्पोरी, जापान का निक्की 225, चीन का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग बढ़त में कारोबार कर रहे हैं। वहीं, रुपया शुरुआती कारोबार में 44 पैसे मजबूत होकर 94.92 प्रति डॉलर पर पहुंच गया है।

ईपीएफओ ने कंपनियों से 28 दिसंबर से पहले पीएफ ट्रस्ट एमनेस्टी के लिए आवेदन करने को कहा

एजेंसी, नई दिल्ली । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने मंगलवार को एक बार फिर कंपनियों से 28 दिसंबर की तय समय-सीमा से पहले पीएफ ट्रस्ट एमनेस्टी के लिए आवेदन करने को कहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना 2026 के तहत भविष्य निधि ट्रस्टों के लिए माफी के प्रावधान पेश किए गए हैं। ये उन ट्रस्टों को एक बार का अवसर देना जिनके पास औपचारिक छूट आदेश नहीं है। ईपीएफओ इसके लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। मंत्रालय ने कहा कि ईपीएफ योजना, 2026 में माफी योजना से संबंधित प्रावधान को एक संक्रमणकालीन उपाय के रूप में शामिल किया गया था, जिसको 29 जून, 2026 को अधिसूचित किया गया था। इन प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे भविष्य निधि (पीएफ) ट्रस्टों को अपनी छूट प्राप्त स्थिति नियमित कराने का एकमुश्त अवसर दिया गया है, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है लेकिन उनके पास कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 अथवा सामाजिक सुरक्षा संहिता (सीओएसएस), 2020 की धारा 143 के तहत जारी औपचारिक छूट आदेश नहीं है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा कि माफी योजना के संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों, जिनमें आवेदन की प्रक्रिया और प्रक्रियागत आवश्यकताएं शामिल हैं, का विवरण 11 जुलाई, 2026 को जारी परिपत्र में दिया गया था।

थोक महंगाई दर सितंबर महीने में बढ़कर रिकॉर्ड 11.39 फीसदी पर पहुंची

एजेंसी, नई दिल्ली

महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को झटका लगने वाली खबर है। खुदरा महंगाई दर के बाद खाद्य पदार्थों, विनिर्मित वस्तुओं और ईंधन एवं बिजली की कीमतों में तेज उछाल से सितंबर में थोक महंगाई दर बढ़कर 11.39 फीसदी पर पहुंच गई है, जो अगस्त में 9.92 फीसदी थी। यह पांच महीने का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित थोक महंगाई दर के जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी है। आंकड़ों अनुसार खाद्य पदार्थों की महंगाई दर अगस्त के 7.05 फीसदी से बढ़कर सितंबर में 8.66



फीसदी हो गई। विनिर्मित वस्तुओं में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई दर भी बढ़कर 9.76 फीसदी के श्रृंखला के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अगस्त में यह 8.37 फीसदी थी। ईंधन एवं बिजली की महंगाई दर सितंबर में 25.85 फीसदी रही, जबकि पिछले महीने अगस्त में यह 22.93 फीसदी रही थी। मंत्रालय ने डब्ल्यूपीआई के आंकड़े जारी करते

हुए कहा कि खनिज तेल (पेट्रोलियम उत्पादों सहित), खाद्य पदार्थों, कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस, कोयले एवं लिग्नाइट, बुनियादी धातुओं, रसायनों एवं रसायनिक उत्पादों, वस्त्रों, रबर एवं प्लास्टिक उत्पादों तथा बिजली के उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी से सितंबर में थोक महंगाई की दर में वृद्धि दर्ज की गई है। सितंबर के अफ इंडिया (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति ने पिछले हफ्ते ही नीतिगत दर रोपो रेट में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 5.50 फीसदी कर दिया था। वहीं, इस सप्ताह की शुरुआत में जारी खुदरा महंगाई दर भी खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के कारण सितंबर में बढ़कर 23 महीने के उच्च स्तर 5.54 फीसदी पर पहुंच गई।

Tata Power Advances 2.8 GW Data Centre Pipeline to Support India's AI Growth

DB Reporter

Jamshedpur : Tata Power is strengthening its position in India's rapidly expanding data centre sector, with an opportunity pipeline exceeding 2.8 GW across renewable energy, transmission and distribution, and integrated infrastructure solutions.

The company is engaging in 29 active workstreams involving 18 leading domestic and international data centre operators as demand for artificial intelligence (AI), cloud computing and digital services continues to rise.

Tata Power's pipeline includes approximately 430 MW of upcoming load under its distribution network, 1,236 MW of transmission-linked opportunities and 1,150 MW of green energy capacity under active engagement.

Leveraging its presence across generation, transmission and distribution, the company aims to offer data centre devel-



opers a comprehensive range of solutions, including powered land, grid connectivity, renewable energy, energy storage, cooling systems and utility infrastructure. These offerings are designed to support hyperscale facilities and next-generation AI-ready digital infrastructure. In the Mumbai Metropolitan Region (MMR), Tata Power is upgrading its 110

kV and 220 kV transmission networks to meet the growing electricity requirements of large data centres. The company is expanding transformation and transmission capacities while developing network redundancy to ensure reliable and uninterrupted power supply. It is also developing new receiving stations and advancing a 400 kV transmission ring network to

create a resilient grid capable of supporting future digital infrastructure. These initiatives form part of Tata Power's ₹15,000 crore Mumbai Grid Upgradation and Expansion Plan.

India's expanding role in global AI and digital infrastructure is expected to drive substantial electricity demand. According to estimates from the Central Electricity Authority cited by the Ministry of Power, AI-led data centres could add around 26.3 GW of power demand by FY2031-32.

The International Energy Agency has also highlighted the growing contribution of emerging economies, including India, to data centre expansion and electricity consumption.

With its integrated energy capabilities and expanding infrastructure investments, Tata Power is positioning itself to address the evolving power requirements of India's digital economy and support the development of large-scale data centres.

India reaffirms Ladakh status as China says it doesn't recognise the UT

New Delhi, Agency: Diplomatic tensions flared again between India and China after Beijing strongly opposed India's decision to officially map and standardise 28 places in Ladakh, including some in Aksai China, and reaffirmed that it does not recognise the Union Territory (UT) of Ladakh. In a swift rebuttal, New Delhi reiterated no amount of Chinese denial can change the established fact that the Ladakh UT is an integral and inalienable part of India.

According to the ministry of home affairs (MHA), which announced the standardisation in a press release on October 2, identifying the places/ geographical features formally on the Survey of India map was aimed at facilitating their accurate recognition and better awareness among the public at large. MEA spokesperson Randhir Jaiswal reiterated the same, saying the MHA statement was self-explanatory.

"The announcement mentions that the twenty-eight (28) places/features located in the UT of Ladakh have been identified with standard place and feature names on the official map of Survey of India, and it has been done in consultation with the Union Territory of Ladakh and local stakeholders," he said.

The Chinese foreign ministry described the Indian move as illegal say-



ing it doesn't change the fact that the western sector of the China-India boundary belongs to China. "China has never recognized the so-called Union Territory of Ladakh unilaterally and illegally established by India, and firmly opposes the so-called standardized names published by India," said spokesperson Mao Ning. However, China itself has renamed places in Arunachal Pradesh on at least half a dozen occasions in the past 10 years, including twice in 2026, to reinforce its claim over the Indian state.

The fresh cartographic tussle comes in the middle of the ongoing normalisation of the bilateral relationship after a military standoff in eastern Ladakh.

'EC should regain credibility': Ashok Lavasa says poll panel must regain public trust amid SIR controversy

New Delhi, Agency: Former election commissioner Ashok Lavasa on Tuesday said the Election Commission of India (ECI) was facing an unprecedented level of controversy and urged the poll body to regain public trust amid protests over alleged irregularities in the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls. Drawing a parallel with cricket, Lavasa said the credibility of an election depended on people believing that the poll panel was impartial.

"If people feel that the umpire is not neutral, they will question the winning team's victory as well," he said while addressing a citizens' convention in Kolkata virtually, according to news agency Media.

Lavasa's remarks came as opposition parties intensified their protests against alleged "vote chori", demanding the resignation of chief election commissioner (CEC) Gyanesh Kumar over the SIR exercise.

Opposition leaders have taken to the streets in recent days and clashed with police in New Delhi.

"The EC should regain its credibility and people's trust. The Election Commission of India, whose position is very high and possibly the highest among all public institutions, is today mired in controversies and people are taking to the streets to protest," Lavasa said.

Questions over dissent within Election Commission: The former elec-

tion commissioner referred to an Indian Express report that election commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi had objected on record at least 14 times over the past 10 months to decisions and orders they said had been issued without their knowledge.

The objections reportedly came even as the nationwide SIR exercise was being overseen by the full commission.

Lavasa questioned the lack of publicly available meeting minutes, saying it was difficult to establish whether decisions had been taken unanimously or by a majority.

"This casts a doubt in the minds of the people whether the decisions of the Election Commission, including on the SIR, were unanimous or taken by majority," he said. He also said the Election Commission had not provided an authentic clarification on the reported differences between its members. "Some press statements have been issued, but those create more questions and generate more doubts than they answer," Lavasa said.

The poll panel has maintained that differing views and observations are a normal part of deliberations in any institution. It has also said that all its orders carry full legal sanction and follow established statutory procedures.

The EC added that all three commissioners, as well as its officers, were authorised to offer suggestions to improve the electoral system.

Sunak meets Modi, hails his leadership as UK-India ties go 'from strength to strength'

New Delhi, Agency: Former UK prime minister Rishi Sunak met Prime Minister Narendra Modi in New Delhi on Tuesday and congratulated him on completing 25 years in public service. Praising PM Modi's commitment and work ethic, Sunak said the UK-India relationship was going from "strength to strength" under his leadership.

In a post on X, Sunak recalled working with PM Modi during his tenure as prime minister and highlighted the importance of closer cooperation between the two countries in trade, technology and artificial intelligence (AI).

"Prime Minister Narendra Modi great to see you in New Delhi today. Congratulations on 25 years in public service, a remarkable achievement. It was a pleasure to work with you when I was Prime Minister," Sunak wrote.

Praising Modi's approach to public service, he added, "Your commitment, your work ethic, your energy is an example to us all."

On bilateral ties, Sunak



said, "The UK India relationship is going from strength to strength under your leadership. Our two countries cooperating more on trade, tech and AI is vital in a less predictable world."

He also expressed confidence in the future of the partnership, writing, "I know that Britain and India will continue to grow ever closer in the years ahead."

Earlier on Tuesday, Sunak spoke about the changing global order and the growing ability of countries such as India and those in the Gulf to pursue independent foreign policy positions amid increasing geopolitical uncertainty.

Speaking at a panel discus-

sion titled "The End of Predictability" at the Bloomberg New Economy Forum 2026 in New Delhi, Sunak said the world was moving away from the multilateral, rules-based framework that had shaped the global economy.

- RishiSunak (@RishiSunak)

"We all grew up investing in, operating in a multilateral rules-based framework, largely enforced by US President Trump is not a cause for that; he's a symptom of that, and the world that we're in now is one where we don't quite know what we've settled down to, and that creates an enormous amount of geopolitical

uncertainty and indeed danger," he said. Sunak also described China's emergence as a strategic competitor to the United States as a significant shift. "So, China is a peer competitor for the US across economic, military, and technological domains. That is a new feature of the world economy," he said.

Meanwhile, India and the UK have agreed to exchange annual data on the utilisation of tariff concessions under their Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). The decision was taken at the 16th meeting of the India-UK Joint Economic and Trade Committee (JETCO) in New Delhi on Monday.

Commerce and industry minister Piyush Goyal and UK business secretary Jonathan Reynolds reviewed progress since the agreement came into force on July 15, 2026. The annual data exchange is intended to support smoother implementation and help more businesses, particularly small and medium-sized enterprises, benefit from the pact.

Sensex jumps 1100 after finance minister's remarks spark LTCG cut hopes

Mumbai, Agency: Finance minister Nirmala Sitharaman Tuesday said the govt was open and keen to "hear" discussions around the long-term capital gains (LTCG) tax as it was "healthy" to have the debate.

The minister, however, declined to be specific on the matter as preparations for the Union Budget in Feb are already underway.

The FM's comments raised investors' hopes of a reduction in LTCG tax and securities transaction tax (STT), a longstanding demand among foreign funds who have been big sellers in the Indian market in the last two years. As a result, after a steady start, stock prices jumped with the sensx finally settling 1.5% or 1,109 points up at 73,034 points while Nifty closed 1.6% or 359 points up at 22,722 points.

RBI steps to check rupee volatility: FM: While responding to an observation that investors, especially foreign funds, were keen on removal of capital gains tax and streamlining of taxation before they started investing in India, Sitharaman said, "Two years ago, we had bought all the asset classes similarly and people thought that I was increasing the tax."



US secretary of state Rubio to travel to India next week energy, strategic partnership and investment in focus

New Delhi, Agency: US secretary of state Marco Rubio will visit Mumbai and Jamnagar from October 17 to 22 as part of a trip to India and Uzbekistan, with talks in India set to focus on strengthening bilateral strategic ties and expanding energy cooperation.

According to a media note issued by the US department of state, Rubio will travel to Samarkand in Uzbekistan before arriving in India for his second official visit to the country this year. During his India visit, Rubio is set to meet senior government officials to strengthen the US-



India strategic partnership, exchange views on regional and global developments, and discuss prospects for enhanced energy cooperation. He will also meet business leaders to explore

opportunities for commercial investment and economic cooperation between the two countries.

Before travelling to India, Rubio will participate in the C5+1 Ministerial in

Uzbekistan, where he is expected to highlight strategic cooperation between Washington and the five Central Asian countries: Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan and the Kyrgyz Republic.

Rubio will also hold bilateral meetings with senior officials from the participating countries. The Uzbekistan leg of his trip will include a US commercial delegation comprising more than 200 business leaders, aimed at strengthening commercial ties between the United States and Central Asia.

Omar, Mehbooba, Mirwaiz oppose bid to enforce uniform Friday sermons

Srinagar, Agency: The J&K Waqf Board's move to introduce uniform Friday sermons across Jammu & Kashmir has drawn fierce criticism in the region from key political figures, including CM Omar Abdullah.

"This is an unacceptable attempt by BJP to interfere in the religious affairs of Muslims and will not be accepted under any circumstances. The BJP-appointed chairperson must immediately halt this misplaced attempt to please her masters," Omar said. Waqf Board chairperson Dr Darakhshan Andrabi belongs to BJP. PDP president Mehbooba Mufti called for the transfer of Waqf administration in J&K to the elected government. "This is the BJP's agenda to harass Muslims. They want to interfere in our religious affairs. Just like the Uniform Civil Code, they also want to impose uniformity in this matter. These are our mosques, built with our people's money. Our imams and maulvis know what to say and when," she said.

On Saturday, Andrabi chaired a meeting of muftis, imams and other religious scholars proposing a committee to identify and finalise topics for Friday sermons in advance and communicate them to mosque imams associated with Waqf-managed institutions across J&K and other mosques. The meeting, according to Andrabi, was attended by around 1,500 imams and Islamic scholars.

Andrabi said the Waqf Board has not



issued any order or directive on the issue. She said religious scholars and imams proposed uniform Friday sermons to address social evils like drug abuse, suicide and late marriages. "All imams and preachers had assembled and there was no role of the Waqf board officials in it," she said.

Rejecting criticism from political figures, Andrabi said Muslim scholars associated with the Waqf Board were qualified to take such decisions and urged politicians to stay out of the matter. "If politicians are of the view that imams should not talk about drug abuse and other evils, then fine," she said. Hurriyat Conference chairman Mirwaiz Umar Farooq, who also heads Muttahida Majlis-e-Ulema (MMU), the largest representative organization of Islamic scholars, imams, and socio-religious bodies in J&K, said MMU strongly rejects any attempt by the Waqf Board to prescribe uniform Friday sermons. "The religious guidance is the domain of ulema and imams, not state-linked bodies.